उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

मेसर्स स्वदेशी कॉटन मिल्स कं., लिमिटेड,

और अन्य

(और संबंधित अपील)

(भगवती, जाफर इमाम और गजेन्द्रगढ़कर जेजे.)

औद्योगिक विवाद-निर्दिष्ट समय से परे किए गए अधिनिर्णय-वैधता-समय के विस्तार और सत्यापन के लिए प्रावधान-निर्माण-उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 27 उत्तर प्रदेश), 6-ए-उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1953 (1953 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश) धारा 3।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत 15 मार्च, 1951 को राज्यपाल द्वारा बनाए गए सामान्य आदेश संख्या 615 के खंड 16 में प्रावधान किया गया है कि न्यायाधिकरण या न्यायनिर्णायक का निर्णय निर्देश की तारीख से 40 दिनों के भीतर सुनाया जाएगा। 19 अगस्त, 1952 और 20 जनवरी, 1953 के आदेशों द्वारा राज्यपाल ने दो औद्योगिक विवादों को निर्णय के लिए भेजा। संदर्भों में उस समय का उल्लेख नहीं किया गया था जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किए जाने थे, लेकिन कहा गया था

कि विवादों का निर्णय आदेश संख्या 615 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना था। पहले संदर्भ में अधिनिर्णय देने की अवधि समय-समय पर 10 मार्च, 1953 तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन दूसरे संदर्भ में समय नहीं बढ़ाया गया था। 18 फरवरी, 1953 को, अधिनिर्णय दिए जाने से पहले, सी.एल. आदेश संख्या 615 के 16 में संशोधन किया गया और 40 दिनों के समय को बदलकर 180 दिन कर दिया गया। पहले मामले में अधिनिर्णय संदर्भ के 180 दिनों के बाद 17 अप्रैल, 1953 को और दूसरे मामले में संदर्भ के 40 दिनों के बाद लेकिन उसके 180 दिनों के भीतर 26 जून, 1953 को दिया गया था। 22 मई, 1953 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1951 लागू हुआ, जिसने पूर्वव्यापी प्रभाव से राज्य सरकार को समय-समय पर अधिनिर्णय देने की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदान की और जिसने कुछ अधिनिर्णयों को भी मान्य किया, जो उन्हें बनाने के लिए मूल रूप से निर्धारित समय के भीतर नहीं दिए गए थे। श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दोनों अधिनिर्णय कानूनी रूप से मान्य नहीं थे क्योंकि वे समय के भीतर नहीं दिए गए थे। अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि सी. एल. आदेश संख्या 615 के 16 में संशोधन किया गया था, संदर्भ के आदेशों को 180 दिनों को निर्दिष्ट करने के रूप में माना जाना चाहिए, जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किए जाने थे, और यह कि, किसी भी मामले में, अधिनिर्णय अध्यादेश 3 द्वारा मान्य किए गए थे।

अभिनिर्धारित किया गया कि पहले मामले में अधिनिर्णय समय से परे प्रस्तुत किया गया था और अमान्य था और अध्यादेश की धारा 3 द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता था, लेकिन दूसरे मामले में अधिनिर्णय, हालांकि समय से परे प्रस्तुत किया गया था, अध्यादेश की धारा 3 (2) द्वारा मान्य किया गया था।

अधिनियम में अधिनिर्णयों को एक निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी और हालांकि संदर्भ के आदेशों में कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया था, लेकिन इसमें कहा गया था कि संदर्भों का निर्णय आदेश संख्या 615, के प्रावधानों के अनुसार किया जाना था। और इस तरह के आदेशों को 40 दिनों को निर्दिष्ट करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किए जाने थे। खण्ड 16 का अगला संशोधन जिसके तहत 40 दिनों के लिए 180 दिनों को प्रतिस्थापित किया गया था, पहले खण्ड 16, के रूप में किए गए संदर्भ के आदेश को प्रभावित नहीं कर सकता था। जैसा कि संशोधित किया गया है, पूर्वव्यापी संचालन नहीं माना जा सकता है।

अध्यादेश की धारा 3 के सही निर्माण पर खंड (1) को अध्यादेश के प्रारंभ से पहले किए गए अधिनिर्णयों को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के सभी आदेशों को मान्य करने के लिए अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए। खंड (3) अध्यादेश के प्रारंभ में लंबित कार्यवाही पर लागू होता है और अध्यादेश द्वारा शुरू की गई अधिनियम की धारा 6 ए को ऐसी कार्यवाही पर

लागू करता है और खंड (2) उन अधिनिर्णयों को मान्य करता है। जिनके खिलाफ अध्यादेश के प्रारंभ में कोई न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं थी और न केवल वे अधिनिर्णय जो अंतिम हो गए थे। नतीजतन, पहले मामले में अधिनिर्णय जिसके खिलाफ अध्यादेश के प्रारंभ से पहले अपील दायर की गई थी और जिस पर अध्यादेश की धारा 3 का खंड (3) लागू होता था, वह गलत था क्योंकि यह समय बढ़ाने की अंतिम तिथि के बाद किया गया था। लेकिन दूसरे मामले में अधिनिर्णय जिसके खिलाफ अध्यादेश के प्रारंभ के बाद अपील दायर की गई थी, अध्यादेश की धारा 3 के खंड (2) द्वारा मान्य किया गया था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील. सं. 1955 का 14 और 15।

1953 के सिविल अपील सं. III-198 और 1953 के III-321 में भारतीय श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, लखनऊ के 30 सितंबर, 1953 के निर्णय से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

एस.एस. धवन, जी.सी. माथुर और सी.पी. लाल, अपीलकर्ताओं के लिए और प्रत्यर्थी संख्या 2 (संघों) ने अपील की शपथ ली।

एच.एन. सान्याल, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल और एस.पी. वर्मा, 1955 की सी.ए. संख्या 14 में प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

सी.ए. में प्रतिवादी संख्या 1 के लिए एन.सी. चटर्जी और राधे लाल अग्रवालः 55 में से 15।

20 नवंबर 1957

न्यायालय का निर्णय इमाम जे॰ द्वारा दिया गया था।

विशेष अनुमति द्वारा दो अपीलों की एक साथ सुनवाई की गई है क्योंकि वे 30 सितंबर, 1953 को भारतीय श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, लखनऊ के एक ही फैसले से उत्पन्न होती हैं, जिसे उसके समक्ष सात अपीलों में पारित किया गया था। चूंकि इस न्यायालय के समक्ष अपीलों में विचार के लिए प्रश्न एक ही है, इसलिए यह निर्णय हमारे समक्ष दोनों अपीलों को नियंत्रित करेगा। 1955 की सिविल अपील संख्या 14 और 15 श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष क्रमशः 1953 की अपील संख्या III-198 और 1953 की III-321 से उत्पन्न होती है।

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह था कि जिन अधिनिर्णयों से उस न्यायाधिकरण के समक्ष सात अपीलें दायर की गई थीं, क्या वे कानून में वैध थे और अधिकार क्षेत्र के साथ किए गए थे। यह वही सवाल है जो हमारे सामने आवेदनों में उठता है।

इन अपीलों में उठाए गए प्रश्न पर विचार करने से पहले कुछ तथ्यों को बताना आवश्यक है। 15 मार्च, 1951 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम

XXVIII) की धारा 3 और धारा 8 के क्लॉज (बी), (सी), (डी) और (जी) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के तहत कई खंडों से युक्त एक सामान्य आदेश बनाया, जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया, 10 मार्च, 1948 के सामान्य आदेश संख्या 781 (एल)/XVIII के सुपर सेशन में। 15 मार्च, 1951 के आदेश की संख्या 1951 के 615 (एल. एल.)/XVIII-7 (एल.एल.) थी, जिसे इसके बाद आदेश संख्या 615 के रूप में संदर्भित किया गया था। इन अपीलों में उठाए गए प्रश्न पर विचार करने से पहले कुछ तथ्यों को बताना आवश्यक है। 15 मार्च, 1951 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम XXVIII) की धारा 3 और धारा 8 के खण्ड (बी), (सी), (डी) और (जी) द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के तहत कई खंडों से युक्त एक सामान्य आदेश बनाया, जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया, 10 मार्च, 1948 के सामान्य आदेश संख्या 781 (एल)/XVIII के स्थान पर। 15 मार्च, 1951 के आदेश की संख्या 1951 के 615 (एल. एल.)/XVIII-7 (एल.एल.) थी, जिसे इसके बाद आदेश संख्या 615 के रूप में संदर्भित किया गया था। आदेश संख्या 615 के खंड 16 के तहत, न्यायाधिकरण या न्यायनिर्णायक का निर्णय 40 दिनों के भीतर सुनाया जाना था, छुट्टियों को छोड़कर, लेकिन उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वार्षिक छुट्टियों को नहीं, किसी भी औद्योगिक विवाद के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गए संदर्भ की तारीख से। इसके प्रावधान ने राज्य सरकार को समय-समय पर अधिनिर्णय प्रस्तुत करने की

अवधि बढ़ाने के लिए अधिकृत किया। 18 फरवरी, 1953 को इस खंड में संशोधन किया गया और 40 दिनों का समय बदलकर 180 दिन कर दिया गया। 17 दिसंबर, 1952 को स्ट्रॉबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम गुट्टा एम. एम. श्रमिक संघ [(1)](1953) एस.सी.आर. 439) के मामले में इस न्यायालय का फैसला सुनाया गया। इस निर्णय के परिणामस्वरूप अधिनियम को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1953 (1953 का अध्यादेश संख्या 1) द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे इसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश के रूप में संदर्भित किया गया था। यह अध्यादेश 22 मई, 1953 को लागू हुआ। अध्यादेश की धारा 2 के प्रावधानों द्वारा धारा 6-ए को अधिनियम में शामिल किया गया। अध्यादेश की धारा 2 में कहा गया हैः

"यू.पी. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद प्रधान अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 6 के बाद, निम्नलिखित को धारा 6-ए के रूप में जोड़ा जाएगा और हमेशा जोड़ा गया माना जाएगा।

अधिनिर्णय प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना। जहां इस अधिनियम के तहत या उसके अनुसरण में किए गए किसी आदेश में कोई अवधि निर्दिष्ट की गई है, जिसमें किसी औद्योगिक विवाद को निर्णय के लिए संदर्भित किया गया है, जिसके भीतर अधिनिर्णय दिया जाएगा, घोषित किया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा, तो यह राज्य सरकार के लिए समय-समय पर ऐसी अवधि को बढ़ाने के लिए सक्षम होगा, भले ही मूल

रूप से निर्धारित या विस्तारित अवधि समाप्त हो गई हो। अध्यादेश की धारा 3 में कहा गया हैः

"संदेहों को दूर करना और मान्यता देना-संदेहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है किः

(1) मूल अधिनियम के तहत इस अध्यादेश के प्रारंभ से पहले धारा 6-ए में निर्दिष्ट विस्तार का कोई आदेश या उसके तहत पारित कोई आदेश जो मूल अधिनियम के तहत वैध और उचित रूप से किया गया होता, यदि धारा 6-ए अधिनियम का हिस्सा होता, तो उसे वैध और उचित रूप से बनाया गया माना जाएगा और

(2) मूल अधिनियम के तहत निर्णय लेने के लिए उक्त प्रारंभ से पहले निर्दिष्ट किसी भी औद्योगिक विवाद में इस अध्यादेश के प्रारंभ से पहले या बाद में दिया गया कोई भी अधिनिर्णय केवल इस आधार पर अमान्य होगा कि मूल रूप से निर्दिष्ट अवधि या उसका कोई विस्तार पहले ही समाप्त हो चुका था।

(3) किसी अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष इस अध्यादेश के प्रारंभ में लंबित प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि धारा 6-ए के प्रावधान सभी भौतिक तिथियों पर लागू थे। निम्नलिखित चार्ट श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सात अपीलों में संदर्भ की तारीख, वह तारीख जिस पर 40 दिनों की

अवधि समाप्त हुई, तिथियां और विस्तार की अवधि, अधिनिर्णय प्रस्तुत करने की तारीख और अपील दायर करने की तारीख, आदेश में दिखाएगा। आदेश संख्या 615 इन प्रावधानों के आधार पर बनाया गया एक सामान्य आदेश था। उस आदेश का खंड 10 राज्य सरकार को किसी भी विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए अधिकृत करता है या यदि राज्य सरकार, विवाद की प्रकृति या पक्ष की सुविधा पर विचार करते हुए, इस प्रकार निर्णय लेती है, तो उस ओर से निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को निर्णय के लिए संदर्भित करती है। खंड 16 ने उस समय को निर्दिष्ट किया जिसके भीतर न्यायाधिकरण या न्यायनिर्णायक का निर्णय सुनाया जाना था, बशर्ते कि राज्य सरकार समय-समय पर अवधि बढ़ा सके। अधिनियम की धारा 6 (1) में विशेष रूप से कहा गया है कि जब कोई प्राधिकरण जिसे किसी औद्योगिक विवाद को अधिनिर्णय या निर्णय के लिए भेजा गया था, अपनी जांच पूरी कर चुका होता है, तो उसे ऐसे समय के भीतर, जो निर्दिष्ट किया जाए, अपना अधिनिर्णय राज्य सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। अतः यह प्रतीत होता है कि अधिनियम के लिए अधिनिर्णय को एक निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, उस समय, अधिनियम की धारा 3 के तहत सुलह या निर्णय के लिए किसी औद्योगिक विवाद के संदर्भ के विशेष आदेश के अभाव में, उस ओर से सरकार द्वारा दिए गए सामान्य आदेश के प्रावधानों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जिस समय के भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाना था, उसे निर्दिष्ट किए बिना निर्णय के लिए एक औद्योगिक विवाद के संदर्भ का

आदेश एक अमान्य संदर्भ आदेश होगा। वास्तव में, अपील के तहत मामलों में निर्देश के आदेशों में कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया था जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाना था। उन्होंने केवल इतना निर्देश दिया कि विवाद का निर्णय आदेश संख्या 615 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यदि संदर्भ के इन आदेशों को आदेश संख्या 615 के खंड 16 के साथ पढ़ा जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने उस समय को निर्दिष्ट किया है जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाना था, संदर्भ की तारीखों से 40 दिन।

आदेश संख्या 615 के खंड 16 का परंतुक, जो राज्य सरकार को समय-समय पर उस अवधि को बढ़ाने का अधिकार देता है, जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाना था, इस न्यायालय द्वारा स्ट्रॉबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम गुल्ला के मामले में अधिनियम की धारा 6 (1) को ध्यान में रखते हुए एक अमान्य प्रावधान पाया गयाः मिल 'श्रमिक संघ [(1)](1953) एस.सी.आर. 439)। यदि मामला वहाँ था तो श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने पाया कि 1953 की अपील संख्या III-198 में निर्णय न केवल विस्तार की अवधि की समाप्ति पर बल्कि संदर्भ की तारीख से 180 दिनों की समाप्ति के लंबे समय बाद भी दिया गया था। अन्य अपीलों के मामले में अधिनिर्णय 40 दिनों की समाप्ति पर लेकिन संदर्भ के 180 दिनों के भीतर दिए गए थे। 1953 की अपील संख्या III-321 और

323 अध्यादेश के प्रारंभ होने के बाद और अन्य इसके प्रारंभ होने से पहले दायर की गई थीं।

स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (1955 की सिविल अपील संख्या 14) के मामले में, राज्यपाल ने 19 अगस्त, 1952 के एक आदेश द्वारा उक्त मिल्स और उसके श्रमिकों के बीच विवाद को आदेश संख्या 615 के प्रावधानों के अनुसार, उसमें बताए गए मुद्दे पर निर्णय के लिए अतिरिक्त क्षेत्रीय सुलह अधिकारी, कानपुर को भेज दिया। कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स (1955 की सिविल अपील संख्या 15) के मामले में, राज्यपाल ने 28 जनवरी, 1953 के अपने आदेश द्वारा उक्त मिल्स और उसके श्रमिकों के बीच विवाद को, उसमें उल्लिखित मुद्दे पर, आदेश संख्या 615 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय के लिए क्षेत्रीय सुलह अधिकारी, लखनऊ को भेज दिया। इन दोनों आदेशों में कोई तारीख निर्दिष्ट नहीं की गई थी जिसके भीतर कानपुर और लखनऊ के क्षेत्रीय सुलह अधिकारियों को अपने अधिनिर्णय प्रस्तुत करने थे। इन आदेशों में केवल इतना कहा गया था कि वे आदेश संख्या 615 के प्रावधानों के अनुसार विवाद का निर्णय लेंगे। आदेश संख्या 615 के खंड 16 के संदर्भ में ही यह कहा जा सकता है कि इन सुलह अधिकारियों के निर्णयों को निर्देश के आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर घोषित किया जाना था और वह निर्देश की तारीख से 40 दिन का होगा। स्वदेशी कपास मिलों के मामले में, समय के विस्तार की कई अवधियाँ थीं,

लेकिन कमलापत मोतीलाल चीनी मिलों के मामले में समय का कोई विस्तार नहीं था, जैसा कि उपरोक्त चार्ट से पता चलेगा।

अधिनियम की धारा 3 के तहत राज्य सरकार, उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के लिए, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, औद्योगिक न्यायालयों की नियुक्ति के लिए और आदेश में दिए गए तरीके से सुलह या निर्णय के लिए किसी भी औद्योगिक विवाद को संदर्भित करने के लिए प्रावधान कर सकती है। आदेश संख्या 615 इन प्रावधानों के आधार पर बनाया गया एक सामान्य आदेश था। उस आदेश का खंड 10 राज्य सरकार को किसी भी विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए अधिकृत करता है या यदि राज्य सरकार, विवाद की प्रकृति या पक्ष की सुविधा पर विचार करते हुए, इस प्रकार निर्णय लेती है, तो उस ओर से निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को निर्णय के लिए संदर्भित करती है। खंड संख्या 16 के परंतुक में उस समय को निर्दिष्ट किया गया था जिसके भीतर न्यायाधिकरण या न्यायनिर्णायक का निर्णय सुनाया जाना था, बशर्ते कि राज्य सरकार समय-समय पर अवधि बढ़ा सके। अधिनियम की धारा 6 (1) में विशेष रूप से कहा गया है कि जब कोई प्राधिकरण जिसे किसी औद्योगिक विवाद को अधिनिर्णय या निर्णय के लिए भेजा गया था, अपनी जांच पूरी कर चुका होता है, तो उसे ऐसे समय के भीतर, जो निर्दिष्ट किया जाए, अपना अधिनिर्णय राज्य सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। अतः यह प्रतीत होता है कि अधिनियम के लिए अधिनिर्णय को एक निर्दिष्ट समय के

भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, उस समय, अधिनियम की धारा 3 के तहत सुलह या निर्णय के लिए किसी औद्योगिक विवाद के संदर्भ के विशेष आदेश के अभाव में, उस संबंध में सरकार द्वारा दिए गए सामान्य आदेश के प्रावधानों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जिस समय के भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाना था, उसे निर्दिष्ट किए बिना निर्णय के लिए एक औद्योगिक विवाद के संदर्भ का आदेश एक अमान्य संदर्भ आदेश होगा। वास्तव में, अपील के तहत मामलों में निर्देश के आदेशों में कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया था जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाना था। उन्होंने केवल इतना निर्देश दिया कि विवाद का निर्णय आदेश संख्या 615 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यदि संदर्भ के इन आदेशों को आदेश संख्या 615 के खंड 16 के साथ पढ़ा जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने उस समय को निर्दिष्ट किया है जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाना था, संदर्भ की तारीखों से 40 दिन।

आदेश संख्या 615 के खंड 16 का परंतुक, जो राज्य सरकार को समय-समय पर उस अवधि को बढ़ाने का अधिकार देता है, जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाना था, इस न्यायालय द्वारा स्ट्रॉबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम गुट्टा मिल श्रमिक संघ (1) के मामले में अधिनियम की धारा 6 (1) को ध्यान में रखते हुए एक अमान्य प्रावधान पाया गया। यदि मामला केवल वहीं रहता, तो अधिनिर्णय, संदर्भ की तारीखों से चालीस दिनों से अधिक समय तक प्रस्तुत किए जाने के

बाद, अमान्य होंगे क्योंकि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिए दिए गए विस्तार की अवधि पर विचार नहीं किया जा सकता था। हालाँकि, अधिनियम को अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया था और धारा 6-ए को अधिनियम में जोड़ा गया था और अध्यादेश की धारा 2 के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की धारा 6-ए को अधिनियम का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। इसलिए अधिनियम की धारा 6 (1) और धारा 6-ए को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 6 (1) में विशेष रूप से कहा गया है कि जांच पूरी होने के बाद निर्णय के लिए निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में अधिनिर्णय एक निर्दिष्ट तिथि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, धारा 6-ए के तहत, राज्य सरकार को समय-समय पर अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया गया था, भले ही मूल रूप से निर्धारित या विस्तारित अवधि समाप्त हो गई हो। इन अपीलों में संदर्भ के आदेश, जैसा कि ऊपर कहा गया है, 40 दिनों को निर्दिष्ट करते हैं जिनके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किए जाने थे। हालाँकि, राज्य सरकार उन अवधियों को बढ़ा सकती है जिनके भीतर धारा 6-ए के तहत अधिनिर्णय प्रस्तुत किए जाने थे, प्रत्येक संदर्भ के मामले में अन्य आदेश जारी करके उस समय को बढ़ाया जा सकता है जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किए जाने थे। मान लीजिए, वास्तव में ऐसा कोई आदेश उस मामले में पारित नहीं किया गया था जो 1955 की सिविल अपील संख्या 15 का विषय है, और उस मामले में जो 1955 की सिविल अपील संख्या 14 का विषय है, हालांकि अधिनिर्णय प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के आदेश दिए गए

थे और अंतिम आदेश ने समय 10 मार्च, 1953 तक बढ़ा दिया था, फिर भी अधिनिर्णय 13 मई, 1953 को प्रस्तुत किया गया था। अतः इन मामलों में अधिनिर्णय एक मामले में संदर्भ क्रम में निर्दिष्ट समय से परे और दूसरे में उस विस्तारित अवधि से परे दिए जाते थे जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाना था।

अपीलार्थी, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से यह आग्रह किया गया था कि आदेश संख्या 615 के खंड 16 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत 40 दिनों के बजाय 180 दिनों का प्रावधान किया गया था, जिसके भीतर एक अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाना था, हमारे सामने मामलों में संदर्भ के आदेशों को 180 दिनों को निर्दिष्ट करने के रूप में माना जाना चाहिए, जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किए जाने थे। दूसरे शब्दों में, खंड 16, हालांकि 18 फरवरी, 1953 को संशोधित किया गया था, लागू होने में पूर्वव्यापी था। आदेश संख्या 615 एक सामान्य आदेश है जिसके तहत औद्योगिक विवादों से निपटने के लिए सुलह बोर्ड और औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की जा सकती है। यह सच है कि खंड 16 में आदेश दिया गया है कि न्यायाधिकरण या न्यायनिर्णायक द्वारा निर्णय एक निर्दिष्ट संख्या के दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए लेकिन यह एक सामान्य निर्देश है। संदर्भ का आदेश एक विशेष आदेश है। यह बता सकता था कि किस तरीके से औद्योगिक विवाद का निर्णय लिया जाना था और यह उस समय को भी निर्दिष्ट कर सकता था जिसके भीतर निर्णय सुनाया

जाना था। जैसा कि हमारे समक्ष मामलों में निर्देश के आदेशों में केवल यह कहा गया था कि उनका निर्णय आदेश संख्या 615 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना था, विवादों का निर्णय इस प्रकार प्रदान किए गए तरीके से किया जाना था और निर्देश के आदेशों को, तदनुसार, 40 दिनों को निर्दिष्ट समय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किए जाने थे। खंड 16 का बाद का संशोधन, जिसके तहत 40 दिनों के बजाय 180 दिनों का प्रावधान किया गया था, जिसके भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाना था, पहले किए गए संदर्भ आदेश को प्रभावित नहीं कर सकता था, जिसके अनुसार अधिनिर्णय 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना था। हम अपीलार्थी की ओर से किए गए निवेदन से सहमत नहीं हो सकते हैं कि खंड 16, जैसा कि संशोधित किया गया है, को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए और पहले जारी किए गए संदर्भ आदेशों को अधिनिर्णय प्रस्तुत करने के लिए 180 दिनों का समय निर्दिष्ट करने के रूप में माना जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 6 (1) इस आशय की है कि जिस प्राधिकारी को किसी औद्योगिक विवाद को निर्णय के लिए भेजा गया है, उसे उस समय के भीतर अपना निर्णय प्रस्तुत करना चाहिए जो निर्दिष्ट किया जाए। अधिनियम की धारा 6-ए के साथ पठित यह धारा, उनके प्रावधानों की उचित व्याख्या पर, यह स्पष्ट करती है कि जिस समय के भीतर अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाएगा, वह संदर्भ के क्रम में निर्दिष्ट अवधि है। इसलिए, खंड 16 का केवल संशोधन संदर्भ क्रम में पहले से निर्दिष्ट अवधि को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए, हमें ऐसा लगता है कि खंड 16 में

संशोधन ने स्थिति को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं किया और हमारे समक्ष मामलों में अधिनिर्णय संदर्भ के आदेश की तारीखों से 40 दिनों के भीतर या अधिनिर्णय प्रस्तुत करने के लिए बढ़े हुए समय के भीतर प्रस्तुत किए जाने थे।

अध्यादेश की धारा 3 का क्या प्रभाव है, यह एक ऐसा विषय है जिस पर अब विचार किया जाना बाकी है। यह धारा संदेहों को दूर करने और अधिनिर्णय प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के आदेशों को मान्य करने के लिए थी। यह कुछ अधिनिर्णयों को मान्य करने के लिए भी था। इस धारा के खंड (1) का अर्थ लगाने में कोई कठिनाई नहीं है। यह अध्यादेश के प्रारंभ से पहले किए गए विस्तार के सभी आदेशों को मान्य करता है जैसे कि अधिनियम की धारा 6-ए हमेशा अधिनियम का हिस्सा रही हो। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 3 के तहत घोषित सामान्य आदेश के तहत किए गए समय विस्तार के आदेश को धारा 6-ए के तहत किया गया माना जाएगा। अध्यादेश की धारा 3 का खंड (3) भी इसके प्रावधानों को समझने में कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं करता है। यह निर्देश देता है कि किसी अधिनिर्णय के विरुद्ध अध्यादेश के प्रारंभ में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय इस तरह किया जाएगा जैसे कि अधिनियम की धारा 6-ए सभी भौतिक तिथियों पर लागू थी।

इस धारा के खंड (1) और (3) केवल अधिनियम की धारा 6-ए के प्रावधानों पर फिर से जोर देते हैं, जो हमारी राय में, उपरोक्त खंडों के अभाव में भी पर्याप्त स्पष्ट हैं। यह अध्यादेश की धारा 3 का खंड (2) है जिसके सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि खंड (2) अपनी शर्तों में सभी अधिनिर्णयोंको शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक था, न कि केवल वे अधिनिर्णय जो श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित अंतिम हो गए थे। खंड के अंत में "जैसे कि धारा 6-ए सभी भौतिक तिथियों पर लागू थी" शब्द अनावश्यक थे और उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। वास्तव में, उनके अनुसार, खंड (2) के प्रावधानों को देखते हुए खंड (3) के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं थी। खंड (2) अध्यादेश के प्रारंभ से पहले या बाद में किए गए सभी अधिनिर्णयोंको मान्य करता है, भले ही वह निर्दिष्ट अवधि जिसके भीतर उन्हें प्रस्तुत किया जाना था या उसका कोई विस्तार पहले ही समाप्त हो चुका था, जहां तक कि उन पर केवल उसी आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था और इसमें किसी अधिनिर्णय के खिलाफ अध्यादेश के प्रारंभ में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में लंबित कार्यवाही भी शामिल होगी।

1955 की सिविल अपील संख्या 15 में प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री एन.सी. चटर्जी ने तर्क दिया कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने सही दृष्टिकोण अपनाया कि अध्यादेश की धारा 3 के खंड (2) में ऐसे मामले

शामिल हैं जहां अधिनिर्णय अंतिम हो गए थे। उन्होंने उस न्यायाधिकरण के निर्णय के समर्थन में निम्नलिखित आधारों पर अपना तर्क आगे बढ़ाया। अध्यादेश की धारा 3 द्वारा इस तरह के स्पष्टीकरण का अर्थ अधिनियम की धारा 6-ए के संबंध में लगाया जाना चाहिए, न कि स्वतंत्र रूप से। यदि कोई अधिनिर्णय धारा 6-ए के दायरे से बाहर किया गया था तो अध्यादेश की पूरी धारा 3 ऐसे मामले में लागू नहीं हो सकती थी। अध्यादेश की धारा 3 (1) ने समय बढ़ाने के उन सभी आदेशों को मान्य किया जो अध्यादेश के प्रारंभ से पहले किए गए थे। इस तरह के आदेशों को वैध रूप से किया गया माना जाना चाहिए जैसे कि धारा 6-ए अधिनियम का एक हिस्सा था। अध्यादेश की धारा 3 (2) को किसी अधिनिर्णय की वैधता पर सवाल उठाने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, जब उसे प्रस्तुत करने या उसके किसी भी विस्तार के लिए निर्दिष्ट अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया था। "मानो धारा 6-ए सभी भौतिक तिथियों पर लागू थी" शब्द केवल यह दर्शाते हैं कि अधिनियम की धारा 6-ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा विस्तार का आदेश दिया जाना चाहिए। अध्यादेश की धारा 3 (2) का उस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं था जहां धारा 6-ए के तहत सरकार की शक्तियों के प्रयोग से स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय दिया गया था। अध्यादेश की धारा 3 (2) और (3) अधिनियम की धारा 6-ए के अधीन थीं।

न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से यह विचार रखा कि अध्यादेश की धारा 3 की उप-धारा (2) और (3) के बीच विरोध था और इसलिए उसने धारा 3 की उप-धारा (2) के दायरे पर एक कृत्रिम प्रतिबंध लगाकर उस विरोध को टालने का प्रयास किया। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि धारा 3 (2) केवल उन अधिनिर्णयों पर लागू होती है जो अंतिम हो गए हैं, न्यायाधिकरण ने इस तथ्य की अनदेखी की कि इस उप-धारा में उन अधिनिर्णयों का उल्लेख किया गया है जो अध्यादेश के प्रारंभ होने के बाद भी दिए जा सकते हैं और यह समझना आसान नहीं है कि अध्यादेश जारी होने की तारीख को इन अधिनिर्णयों के साथ कितनी अंतिमता को संलग्न किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने इस तर्क से भी प्रभावित महसूस किया कि यदि अध्यादेश के प्रारंभ की तारीख में लंबित अधिनिर्णयों के खिलाफ अपील या कार्यवाही पर धारा 6-ए लागू होती है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वही प्रावधान अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होना चाहिए जो अध्यादेश के शुरू होने के बाद अधिनिर्णयों के खिलाफ लिया जा सकता है। हालाँकि, इस दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य की अनदेखी की कि धारा 3 (3) जानबूझकर अध्यादेश के प्रारंभ में लंबित एक अधिनिर्णय के खिलाफ कार्यवाही तक सीमित है और कोई अन्य नहीं।

हमारी राय में इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य उस समय के विस्तार के आदेशों को मान्य करना था जिसके

भीतर एक अधिनिर्णय प्रस्तुत किया जाना था और साथ ही इसकी वैधता पर केवल इस आधार पर सवाल उठाए जाने से रोकना था कि यह निर्दिष्ट समय से परे प्रस्तुत किया गया था या इसका कोई विस्तार किया गया था। समय बढ़ाने के आदेश के अलावा अध्यादेश का उद्देश्य कम से कम तीन स्थितियों से निपटना था जहां तक एक अधिनिर्णय प्रस्तुत करने का संबंध था। एक वह था जहां अध्यादेश के प्रारंभ से पहले एक अधिनिर्णय प्रस्तुत किया गया था और जिसके खिलाफ अध्यादेश के प्रारंभ में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी; दूसरा वह था जहां अध्यादेश लागू होने के बाद एक अधिनिर्णय प्रस्तुत किया गया था। इन मामलों को अध्यादेश की धारा 3 के खंड (2) द्वारा निपटाया गया था। तीसरा मामला वह था जिसमें अध्यादेश के प्रारंभ से पहले एक अधिनिर्णय प्रस्तुत किया गया था, जिसके खिलाफ अध्यादेश के लागू होने से पहले अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष एक कार्यवाही लंबित थी। अध्यादेश की धारा 3 (3) का मसौदा इस तरह तैयार किया गया था कि यह किसी अधिनिर्णय के खिलाफ पहले से लंबित न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करे। इसने केवल यह निर्देश दिया कि ऐसी कार्यवाही का निर्णय इस तरह किया जाना चाहिए जैसे कि धारा 6-ए अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से ही इसका हिस्सा रही हो। हालाँकि, जहाँ किसी अधिनिर्णय के खिलाफ कोई न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं थी, वहाँ अध्यादेश का इरादा यह था कि अधिनिर्णय पर केवल इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि इसे प्रस्तुत करने या उसके किसी

विस्तार के लिए निर्दिष्ट अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि अध्यादेश की धारा 3 (2) को खुशी से नहीं कहा गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह जल्दबाजी में किए गए विधान का परिणाम है, हम सोचते हैं कि इसके प्रावधानों के उचित निर्माण पर इसका अर्थ स्पष्ट है और इसके प्रावधानों और धारा के खंड (3) के प्रावधानों के बीच कोई वास्तविक संघर्ष नहीं है। "मानो धारा 6-ए सभी भौतिक तिथियों पर लागू थी" शब्दों को कुछ अर्थ दिया जाना चाहिए और उन्हें अनावश्यक नहीं माना जा सकता है जैसा कि अपीलार्थियों की ओर से सुझाव दिया गया है। उन्हें किसी कार्रवाई या की गई कार्यवाही, जारी किए गए निर्देश या किसी अधिनिर्णय के अनुसरण में या उस पर प्रयोग की गई अधिकारिता के संदर्भ में माना जाना चाहिए, हालांकि, अधिनियम की धारा 6-ए का इससे कोई लेना-देना नहीं है और ये शब्द खंड के उस हिस्से पर लागू नहीं हो सकते हैं। ये शब्द उस मामले को भी संदर्भित नहीं कर सकते हैं जहां अधिनिर्णय निर्दिष्ट अवधि से परे किया गया है और जिसमें समय बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है क्योंकि अधिनियम की धारा 6-ए ऐसे मामले पर लागू नहीं होती है। इसलिए, प्रश्नगत शब्द केवल खंड के उस भाग पर लागू हो सकते हैं जो अधिनिर्णय प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने को संदर्भित करता है, जो अधिनियम की धारा 6-ए का एकमात्र उद्देश्य है। हमारी राय में, यदि अध्यादेश की धारा 3 (2) को इस तरह से पढ़ा जाता है तो इसका एक बोधगम्य अर्थ दिया जाता है जो अधिनियम की धारा 6-ए के अनुरूप है और अध्यादेश की धारा 3 (3) के साथ टकराव में नहीं है। धारा 3 (2) में

निर्दिष्ट अधिनिर्णय वे अधिनिर्णय हैं जिनके खिलाफ अध्यादेश के प्रारंभ में कोई न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं थी। हमारी राय में, धारा 3 (2) और (3) के प्रावधान एक दूसरे के साथ संघर्ष में नहीं हैं। हम श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि धारा 3 (2) केवल उन अधिनिर्णयों को संदर्भित करती है जो अंतिम हो गए थे।

अध्यादेश की धारा 3 के प्रावधानों का अर्थ निकालने के बाद, अब हमारे समक्ष अपीलों पर विशेष रूप से विचार करना आवश्यक है। श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण की अपील संख्या, जिसमें से 1955 की सिविल अपील संख्या 14 उद्भूत होती है, अध्यादेश के प्रारंभ से पहले दायर की गई थी और अध्यादेश की धारा 3 (3) के आधार पर अपील का निर्णय इस तरह किया जाना था जैसे कि धारा 6-ए के प्रावधान सभी भौतिक तिथियों पर लागू थे। ऐसी अपील के लिए अध्यादेश की धारा 3 के खंड (2) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः यह अपील खंड (3) द्वारा शासित होगी। चूंकि इस मामले में, अधिनिर्णय 13 मई, 1953 को प्रस्तुत किया गया था, और विस्तार की अंतिम तिथि ने 10 मार्च, 1953 तक अधिनिर्णय प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था, इसलिए अधिनिर्णय समय से परे प्रस्तुत किया गया था और इसलिए, अमान्य था क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र के बिना किया गया था।

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण की 1953 की अपील संख्या (3) 321 से उत्पन्न 1955 की सिविल अपील संख्या 15 में, अध्यादेश के प्रारंभ के

बाद उस न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई थी। अधिनिर्णय उस अवधि के बहुत बाद प्रस्तुत किया गया था, अर्थात् 40 दिन, जिसके भीतर इसे प्रस्तुत किया जाना था और समय बढ़ाने का कोई आदेश नहीं था। अतः इस अपील पर अध्यादेश की धारा 3 (2) लागू होगी न कि धारा 3 (3)। परिणामस्वरूप इस मामले में अधिनिर्णय को अध्यादेश की धारा 3 (2) के प्रावधानों के आधार पर मान्य किया गया है और इसकी वैधता पर केवल इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि इसे उस अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया था। जिसके भीतर इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

परिणाम में, 1955 की सिविल अपील संख्या 14 को व्यय के साथ खारिज कर दिया जाता है और 1955 की सिविल अपील संख्या 15 को व्यय के साथ अनुमति दी जाती है और अपील संख्या III-321/53 में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को खारिज करने से पहले अनुमति दी जाती है।

1955 की अपील सं. 14 खारिज कर दी गई।

1955 की अपील सं. 15 की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सपना राजपुरोहित द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।